RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : मंगलवार 24 अक्टूबर 2023 वर्ष 05 अंक 182 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक रोकठोक लेखनी

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

दशहरा पर सुनाई देगी हिंदुत्व और आरक्षण की गूंज

छह आयोजनों में किसका क्या दांव पर

मुंबई, दशहरा और सियासी सभाओं का आयोजन, महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नई बात नहीं है. लेकिन इस साल दशहरे के दिन (मंगलवार को) राज्य में एक-दो नहीं, बल्कि छह अलग-अलग राजनीतिक सभा आयोजित हो रही हैं.

राज्य में बदले राजनीतिक हालात, विचारधाराओं की लड़ाई, आरक्षण और सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर विवाद के मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल और विपक्षी गठबंधन एक दूसरे के आमने-सामने हैं. राजनीति के कई जानकारों की राय है कि इन सभी कार्यक्रमों से ऐसे संदेश सामने आ सकते हैं जिनका राज्य सियासत पर असर देखने को मिल सकता है.

1. शिव सेना के ठाकरे गुट की सभा, स्थान- शिवाजी पार्क, दादर : शिव सेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने 30 अक्टूबर 1966 को, शिवाजी पार्क में पहली दशहरा सभा आयोजित की. इस साल भी शिव सेना के ठाकरे गुट की दशहरा सभा दादर के शिवाजी पार्क में होगी.

2. शिंदे की शिव सेना का समारोह, स्थान- आजाद मैदान, दक्षिण मुंबई : पिछले साल से ही शिव सेना के प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे अलग से दशहरा सभा का आयोजन कर रहे हैं. इस साल का दशहरा मेला, शिव सेना के शिंदे गुट के लिए भी उतना ही अहम है.

3. रोहित की संघर्ष यात्रा और शरद पवार की सभा, स्थान- पुणे : एनसीपी में फूट के बाद अध्यक्ष शरद पवार एक बार फिर मैदान में उतर गए हैं और पार्टी को खड़ा करने का काम शुरू कर दिया है. अजित पवार और उनके साथ बड़ी संख्या में विधायकों के साथ छोड़ने के बाद शरद पवार के पोते विधायक रोहित पवार ने राज्यव्यापी संघर्ष यात्रा की घोषणा की है.

4. पंकजा मुंडे का आयोजन, स्थान- भगवान भक्ति गढ़ : दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे ने बीड के भगवान भक्ति गढ़ में दशहरा सभा की परंपरा शुरू की थी. इसके बाद उनकी बेटी और अब बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव पंकजा मुंडे ने भी इस परंपरा को जारी रखते हुए भगवान भक्ति गढ़ में दशहरा सभा का आयोजन शुरू किया.

5. संघ का विजयादशमी उत्सव, स्थान- नागपुर, आरएसएस मुख्यालय : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर में हर साल विजयादशमी मनाई जाती है. आरएसएस की स्थापना 1925 में विजयादशमी के ही दिन हुई थी. उस दिन, आरएसएस का एक मार्च होता है, एक ड्रिल के बाद आरएसएस नेताओं का संबोधन होता है.

6. धनगर आरक्षण के लिए जुटान, स्थान- चौंडी, अहमदनगर : मराठा आरक्षण का मुद्दा सरकार के सामने है. ओबीसी समुदाय का विरोध और एसटी वर्ग से आरक्षण पाने के लिए धनगर समुदाय ने भी आंदोलन छेड़ा हुआ है. फिलहाल ये लगता है कि राज्य में एक बार फिर से आरक्षण की राजनीति शुरू हो गई है. धनगर समुदाय की यशवंत सेना ने इस समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर अहमदनगर ज़िले के चौंडी में दशहरा सभा के आयोजन का फैसला किया है.

केमिकल इंजीनियर चला रहा था ड्रग्स फैक्ट्री! 500 करोड़ की ड्रग्स बरामद

अहमदाबादः महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ड्रग्स के एक बड़े कारोबार का पदार्फाश हुआ है. अहमदाबाद पुलिस और राजस्व खुफिया निदेशालय ने शनिवार को पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में एक अभियान के तहत औरंगाबाद से एक केमिकल इंजीनियर को गिरफ्तार किया है. दरअसल सूरत के मूल निवासी पर ड्रग्स की फैक्ट्री चलाने के आरोप है. उसकी खुद की फैक्ट्री थी, जहां वह ड्रग्स तैयार करता था. इंजीनियर मुंबई में विशेष और हाई-प्रोफाइल रेव पार्टियां सहित अन्य शहरों में ड्रग्स की आपूर्ति करता था. पुलिस ने औरंगाबाद में इंजीनियर के ठिकाने से 23,000 लीटर कैमिकल का भंडार जब्त किया है. यह एक ठंडा कॉकटेल है, जो नशीले पदार्थों को केटामाइन, मेफेड्रोन और कोकीन के अवैध उत्पादन के लिए बनाया गया था. राजस्व खुफिया निदेशालय सूत्रों के अनुसार इस संयुक्त ऑपरेशन में 23 किलोग्राम कोकीन, लगभग 17 किलोग्राम मेफेड्रोन, और 4.3 किलोग्राम केटामाइन जब्त किया गया है.

बीयर की बिक्री में गिरावट

सरकार ने किया कमिटी का गठन

मुंबई, महाराष्ट्र सरकार ने एक कमिटी का गठन किया है. महाराष्ट्र सरकार ने कमिटी का गठन इस बात की जांच करने के लिए किया कि राज्य में अचानक से बीयर की बिक्री में गिरावट कैसे आ गई है. मतलब एक तरफ जहां ज्यादातर राज्यों में इस बात के लिए कमिटी गठित की जा रही है कि समाज में शराब के बढ़ते इस्तेमाल को कैसे रोका जाए वहीं, महाराष्ट्र सरकार को इस बात की चिंता सता रही है कि राज्य को लोगों ने बीयर पीना क्यों कम कर दिया है?

हाल ही में बीयर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने बीयर पर उत्पाद शुल्क में कटौती की मांग को लेकर राज्य सरकार से संपर्क किया था. सरकार के सामने अपनी समस्या रखी और अवगत कराया कि कैसे अल्कोहल की मात्रा के आधार पर तुलना करने पर बीयर पर उत्पाद शुल्क की दर अन्य शराब की तुलना में अधिक है. साथ ही बीयर पर उत्पाद शुल्क की दर कम करने वाले अन्य राज्यों को राजस्व वृद्धि के मामले में फायदा हुआ है. जिसके बाद सरकार ने समिति गठित करने का निर्देश दिया.

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव (राज्य उत्पाद शुल्क) की अध्यक्षता में 5 लोगो की समिति गठित की गई. समिति में राज्य के आला अधिकारियों समेत बीयर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि भी शामिल है. समिति का काम इस बात का अध्ययन करना होगा कि राज्य में बीयर उद्योग के माध्यम से राज्य का राजस्व कैसे बढ़ाया जाए, राज्य में कम हो रहे बीयर के बिक्री को किस तरह से बढ़ाया जाए और सरकार को इससे राजस्व अर्जित करने में कितनी मदद मिलेगी.

मराठा आरक्षण पर उबाल के बीच मुसलमानों में भी हलचल, रिजर्वेशन पर एक्शन की तैयारी

मुंबई, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर विवादों के बीच मुस्लिम आरक्षण की मांग भी जोर पकड़ रही है. मराठा समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) श्रेणी के तहत आरक्षण की वकालत कर रहा है, जिसको लेकर आरक्षण की नीतियों पर चर्चा और बहस चल रही है. मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी मुंबई में बीते दिन एक अहम बैठक हुई है, जहां देशभर से मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे. बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नसीम खान ने भी शिरकत की.

कांग्रेस नेता नसीम खान ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है. मराठा आरक्षण के साथ-साथ मुस्लिम आरक्षण का भी सवाल था. मराठा आरक्षण की मांग कानूनी दांव-पेंच में फंस गई और मुस्लिम आरक्षण की डिमांड जारी रही. समय-समय पर वे अपनी मांगें रखते रहे हैं. नसीम खान का कहना है कि मुस्लिम आरक्षण धर्म के नाम पर नहीं मांगा जा रहा है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक हालात, पिछड़ापन के आधार पर मांगा जा रहा है. महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण की मांग मुस्लिम समुदाय में सामना की जाने वाली सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और ऐतिहासिक अन्याय में निहित है. समर्थकों का तर्क है कि राज्य में मुसलमानों को सामाजिक और आर्थिक

नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुंच काफी सीमित है. ऐतिहासिक रूप से, न केवल महाराष्ट्र में बल्कि भारत के कई हिस्सों में, मुस्लिम समुदाय को भेदभाव और हाशिए का सामना करना पड़ा है.

आरक्षण की मांग कर रहे मुसलमान कहते हैं कि उन्हें ठीक ढंग से सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सामाजिक स्तर पर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता. आरक्षण से मुस्लिम समाज को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा और इससे वह राजनीतिक रूप से भी सशक्त हो पाएंगे. इससे समुदाय का भी उत्थान हो सकता है. जैसा कि मुंबई की मीटिंग में चर्चा की गई है कि आरक्षण की डिमांड असल में आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर है, जिससे समुदाय का डेवलपमेंट भी हो सकता है. समर्थकों का तर्क है कि आरक्षण से वंचित मुस्लिम समुदायों का शिक्षा, रोजगार और अन्य संसाधनों तक बेहतर पहुंच हो सकता है.

संपादकीय / लेख

नवाज शरीफ की वापसी

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके PML (N) के सबसे बड़े नेता नवाज शरीफ का स्वदेश लौटना पड़ोसी देश की राजनीतिक स्थिरता के लिहाज से एक बड़ी घटना है। इसमें दो राय नहीं कि वह अपने देश के एक लोकप्रिय और कद्दावर नेता रहे हैं। लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि उन्हें बहुचर्चित पनामा पेपर्स लीक होने, सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री पद के अयोग्य बताए जाने, किसी भी तरह का सार्वजनिक पद लेने पर आजीवन रोक लगने और भ्रष्टाचार के मामलों में सात साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद सेहत के आधार पर लंदन जाने की इजाजत मिली थी। चार साल बाद जब वह लौटे हैं तो हाईकोर्ट से 24 अक्टूबर तक की प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई है, इस बीच वह अदालत में हाजिर होंगे और माना जा रहा है कि उन्हें राहत भी मिल जाएगी। इस तरह की उम्मीदों का आधार यह धारणा है कि उनकी वापसी की योजना को पाकिस्तानी फौज की मंजूरी मिली हुई है। फौज की इच्छा और इजाजत से ही यह संभव हुआ है कि जो नवाज शरीफ लंदन जाने के बाद पिछले चार वर्षों के दौरान पाकिस्तान वापसी की सोच भी नहीं पा रहे थे, वह बाइज्जत न केवल अपने देश वापस लौट आए हैं बल्कि आते ही राजनीतिक रैलियां भी करने लगे।

जनवरी के आखिर में ही वहां चुनाव होने हैं और लोकप्रियता में सबसे आगे चल रहे ढळक के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी इसमें शामिल होंगे। फौज से बढ़ते मतभेदों के बाद पद छोड़ने को मजबूर हुए इमरान खान को भ्रष्टाचार के मामलों में जेल भी हो गई, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनके कन्विक्शन पर स्टे दे दिया जिसके बाद उनके चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। जाहिर है, ऐसे में इमरान खान की चुनावी जीत की संभावना समाप्त करना न केवल उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के लिए बल्कि पाकिस्तानी फौज के लिए भी जरूरी है। साफ है कि एक समय में जिस नवाज शरीफ की लोकप्रियता पाकिस्तानी फौज की आंखों में चुभने लगी थी, वही नवाज शरीफ आज उसे इमरान खान को रास्ते से हटाने का जरिया बनते दिख रहे हैं। यह हो पाएगा या नहीं, यह तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही साफ होगा, लेकिन फिलहाल नवाज शरीफ की वापसी ने वहां के चुनावी मुकाबले को दिलचस्प जरूर बना दिया है। हालांकि चुनावी हार-जीत से ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव से जीत कर आया नेतृत्व पाकिस्तान को आर्थिक संकट के दलदल से निकाल पाएगा और क्या वहां लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती मिल पाएगी। पहले सवाल का जवाब कथनी से नहीं सत्तारूढ़ होने वाले नेता की करनी से मिलेगा लेकिन जहां तक दूसरे सवाल की बात है तो जब तक अपनी मर्जी से नेताओं को सत्ता से हटाने और उन्हें वापस ला बिठाने का पाकिस्तानी फौज का खेल चलता रहेगा, तब तक उस मोर्चे पर कोई उम्मीद नहीं की जा सकती।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

दलालों के चंगुल में फंसे मनपा अयुक्त

पहले भरो सभी टैक्स फिर मुलाकात करेगें आयुक्त

भिवंडी मनपा आयुक्त का तुगलकी फरमान से नागरिकों में आक्रोश

मुस्तकीम खान

भिवंडी : भिवंडी महानगर पालिका प्रशासक व आयुक्त अजय वैद्य हमेशा अपने फरमान को लेकर सुर्खीयों और चर्चा में रहते हैं ।इस बार कार्यालय में टपाल संबंधी सूचना को लेकर शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आयुक्त कार्यालय की इस सूचना मनपा आयुक्त अजय वैद्य से यदि किसी नागरिक को मिलना है तो वह पहले अपने मनपा के सभी टाइप्सन का भुगतान कर उसकी रसीद लेकर मनपा कार्यालय में जाए उसे देखने के बाद ही मनपा आयुक्त से जरूरतमंद व्यक्ति मुलाकात कर पाएगा। आयुक्त के इस फरमान को लेकर कई बुद्धिजीवियों ने तुगलकी फरमान करार दिया है और कड़ी नाराजगी व्यक्त की है।इस नए फरमान को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर प्रवक्ता खान मलिक नियाज ने आयुक्त की कार्यशैली पर प्रश्न उठाते हुए राज्य के मुख्यमंत्री सहित मुख्य सचिव कार्यालय में निवेदन पत्र देकर शिकायत की है कि नागरिकों की शिकायतें आयुक्त सुनते नहीं,उन्होंने बताया कि नये डीपी प्लान में अनेक कमियां है इन कमियों को दूर करने में बड़ा भष्ट्राचार होने की सम्भावना है।

मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में मलिक ने बताया है कि शहर के नाले व नालियों से अधिकांश चेंबर गायब है। जिसके कारण महिलाएं बच्चे और दो पहिया वाहन चालक गिर कर जख्मी हो रहे है। छोटे नाले सहित नालियों की बराबर सफाई नहीं होने से सीवर का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इस गंदे पानी से नागरिक, महिलाएं सहित स्कूली बच्चों की आवाजाही लगी रहती है। जन समस्या के बारे में शिकायत दर्ज करवाने के बाद समस्याओं का निपटारा नहीं किया जाता है। इसके साथ उन्होंने पालिका आयुक्त अजय वैद्य पर गंभीर आरोप लगाया है कि आयुक्त अजय वैद्य मोटरसाइकिल से शहर के विभिन्न क्षेत्रों के गल्ली व मोहल्ले में घूम रहे है। वही पर प्रभाग अधिकारियों से फुल रिफील एवं हाफ रिफील आदि जैसे कोड में बातें कर रहे है। अब नए फरमान के मुताबिक मनपा आयुक्त कार्यालय में नागरिकों की तभी एंट्री मिलेगी जब उनका हाउस टैक्स व पानी टैक्स भरा हुआ रहेगा । दूसरा अगर आपको अपनी शिकायत आयुक्त वैद्य से मुलाकात कर दर्ज करानी है तो आप सप्ताह में दो दिन सोमवार व शुक्रवार दोपहर 4 बजे से शाम 5 बजे तक यानी केवल एक घंटे ही मुलाकात कर सकते है इसके लिए सबसे पहले आपको हाउस व पानी टैक्स बकाया राशि का पूर्ण भुगतान कर सबूत के लिए भरे हुए हाउस टैक्स की रसीद साथ में रखना अनिवार्य होगा।भिवंडी मनपा आयुक्त अजय वैद्य कार्यालय के बाहर रोज नागरिकों की भीड़ जमा हो रही है अनेक नागरिकों को बिना मिले वापस जाना पड़ रहा है। जिसके कारण नागरिकों में आयुक्त के खिलाफ तीव्र आक्रोश व्याप्त है। वहीं मनपा आयुक्त पत्रकारों का फोन नहीं रिसीव करते हैं कुछ गिने चुने मुंह लगे पत्रकार हैं जिसे वह जरूरत के मुताबिक बात करते हैं। वहीं अगर आयुक्त कार्यालय या बंगले का सीसी कैमरा चेक किया जाये तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जायेगा । उन्होंने अपना मोबाइल नंबर देने से पहले यह पहले ही कह दिया है कि यदि फोन नहीं उठाऊंगा तो बुरा मत मानिएगा । अब समस्या यह है कि किसी मुद्दे पर या समस्या पर उनकी राय या पक्ष जानकर समाचार पत्र में छापना हो तो पत्रकार कौन सा रास्ता अपनाए , या उसे भी टैक्स भरी हुई पावती लेकर ही मिलने दिया जाएगा इस बात का खुलासा होना अभी बाकी है।

मुंबई की एक अदालत ने पुणे के गिरफ्तार ड्रग माफिया ललित पाटिल की पुलिस हिरासत 27 अक्टूबर तक बढ़ाई...

मुंबई : मुंबई की एक अदालत ने पुणे के गिरफ्तार ड्रग माफिया ललित पाटिल की पुलिस हिरासत 27 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। ससून अस्पताल में भर्ती पाटिल 2 अक्टूबर को पुणे पुलिस के चंगुल से भाग गया था। उसे मुंबई पुलिस की एक टीम ने चेन्नई के पास से गिरफ्तार किया था। उसे 17 अक्टूबर को मुंबई लाया गया और पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पहली रिमांड समाप्त होने के बाद, उसे सोमवार को अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया गया, जिसने उसकी पुलिस हिरासत शुक्रवार तक बढ़ा दी। पुणे में इसी मामले में पाटिल के खिलाफ दर्ज मामलों के लिए उसकी हिरासत की मांग के लिए पुणे पुलिस की एक टीम भी मुंबई में है।

तीन पत्ता जुगार अड्डे पर पुलिस का छापा,

चार पर मामला दर्ज

मुस्तकीम खान

भिवंडी : भिवंडी नारपोली पुलिस ने वेहलेगांव में तीन पत्ता नामक जुगार खेल रहे चार जुआरियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिनके पास से पुलिस ने जुआ की रकम 5 हजार 700 रुपए भी जप्त की है। पुलिस के मुताबिक पिंपलास स्थित वेहलेगांव में उत्तम रमेश पाटील के बेड़े में कुछ लोगों के जुगार खेलने की जानकारी पुलिस को मिली थी। सूचना मिलते ही नारपोली पुलिस ने उक्त बेड़ा पर छापा मारकर कार्रवाई की। परंतु पुलिस को देख तीन पत्ता जुगार खेल रहे लोग भाग खड़े हुए।इस कार्रवाई में पुलिस ने जुगार में लगाई गई रकम 5,700 रुपए जप्त कर उत्तम रमेश पाटील 28 वर्ष, पप्पू शिवदास पाटील 30 वर्ष, विपनेश कैलाश पाटील 21 वर्ष और प्रेम भरत म्हात्रे 23 वर्ष के खिलाफ महाराष्ट्र जुगार एक्ट की कलम 123 (अ) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस उपनिरीक्षक नवले कर रहे है।

युवक की आत्महत्या से मौत, नोट में लिखा है 'मराठा आरक्षण के लिए बलिदान'

महाराष्ट्रः महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के 24 वर्षीय युवक, शुभम पवार ने मराठा आरक्षण के लिए अपने बलिदान का दावा करते हुए एक नोट छोड़ कर अपनी जान ले ली। त्योहारी सीजन के लिए नांदेड़ लौटे पवार ने जहर खा लिया, जिससे उनका परिवार सदमे में है। उनकी दुखद मौत हाल ही में मनोज जारांगे के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद मराठा आरक्षण की मांग से संबंधित चौथी आत्महत्या थी।

मुंबई में छोटे-मोटे काम करने वाला पवार अपने परिवार को अपनी बहन से मिलने की सूचना देने के बाद लापता हो गया। चिंतित परिवार के सदस्यों ने उसके लापता होने की सूचना पुलिस को दी। एक खोज उन्हें तमसा रोड तक ले गई, जहां झाड़ियों में पवार का निर्जीव शरीर पाया गया।

पुलिस को उसके पास एक सुसाइड नोट और एक कीटनाशक की बोतल मिली, जो उस हताशा को रेखांकित करती है जिसके कारण उसने यह कठोर कदम उठाया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा समुदाय के लिए नौकरी और शिक्षा आरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। आत्महत्या विरोधी संदेश में उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे चरम कदम उठाने से पहले अपने परिवार और प्रियजनों के बारे में सोचें।

''आज मैं अपील करना चाहता हूं कि मराठा समुदाय के दो लोगों ने आत्महत्या कर ली, मैं भी मराठा समुदाय से हूं और एक किसान का बेटा हूं, जिन लोगों ने आत्महत्या की है, उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। कृपया ऐसे कदम उठाने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचें।, ''सीएम शिंदे ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार मराठा समुदाय के साथ खड़ी है और मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है, उन्होंने कहा कि आरक्षण देना सरकार की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा, ''मराठा समुदाय को आरक्षण देना सरकार की जिम्मेदारी है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण पर राज्य सरकार की सुधारात्मक याचिका स्वीकार करने के साथ, मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की एक बड़ी खिड़की खुल गई है।'' जोड़ा गया. पवार के निधन से मराठा समुदाय के भीतर गंभीर घटनाओं की एक श्रृंखला जुड़ गई है। इससे पहले, 45 वर्षीय कोटा कार्यकर्ता सुनील कावले मुंबई में मृत पाए गए थे, जो आरक्षण के मुद्दे पर उनके बलिदान की प्रतिध्वनि करते हुए एक नोट छोड़ गए थे। इसी तरह, सुदर्शन कामारिकर और किसन माने ने अपना जीवन समाप्त कर लिया, उनकी निराशा कोटा मुद्दे पर सरकार की कथित निष्क्रियता के कारण थी।

मुंबई के कांदिवली में बहुमंजिला इमारत में भीषण आग; 2 की मौत, 3 बुरी तरह झुलसे

मुंबई : मुंबई के कांदिवली पश्चिम में सोमवार दोपहर एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह झुलसे हैं। घटना पावन धाम वीणा संतूर इमारत में लगी । आग लगने की सूचना पर दमकल की करीब 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग पर काबू पा लिया गया है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। आग लगने के कारणों की जांच जारी है।

मरने वालों में महिला और बच्चा शामिल

पुलिस ने बताया कि आग दोपहर में 12 बजे के आसपास लगी थी, जिस पर 2 बजे तक काबू पा लिया गया। इस दौरान इमारत की कई दुकानें जलकर खाक हो गईं। मृतकों में एक महिला और एक बच्चा शामिल हैं, जिनकी पहचान ग्लोरी वालफटी और जोसु जेम्स रॉबर्ट के रूप में हुई है। तीनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रथमदृष्टया आग का कारण शॉर्ट सर्किट लग रहा है।

मुंबई की वायु गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी में

मुंबई : मुंबई वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली, सफर-इंडिया के अनुसार, सोमवार सुबह मुंबई में हवा की गुणवत्ता 127 के वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ 'मध्यम' श्रेणी में दर्ज की गई। पिछले सप्ताह मंगलवार को मुंबई में हवा की गुणवत्ता 115 के वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ 'मध्यम' श्रेणी में दर्ज की गई थी। इस महीने की शुरूआत में मुंबई ने अपनी वायु गुणवत्ता 'अच्छी श्रेणी' में दर्ज की थी। हालाँकि, शहर में गर्मी में वृद्धि देखी गई और एक सप्ताह तक औसत दैनिक अधिकतम तापमान 32 और 34 डिग्री के बीच रहा, जिससे हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में गिर गई।

वायु गुणवत्ता सूचकांक लोगों को समझने में आसान शब्दों में वायु गुणवत्ता की स्थिति को प्रभावी ढंग से बताने का एक उपकरण है। अदकी छह श्रेणियां हैं: अच्छा + संतोषजनक, मध्यम रूप से दूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर। इनमें से प्रत्येक श्रेणी का निर्णय वायु प्रदूषकों के परिवेशीय सांद्रण मूल्यों और उनके संभावित स्वास्थ्य प्रभावों (स्वास्थ्य कट-ऑफ बिंदु के रूप में जाना जाता है) के आधार पर किया जाता है। अदकपैमाने के अनुसार, 0 और 50 के बीच वायु गुणवत्ता नियंत्रण को ''अच्छा'', 51 और 100 के बीच ''संतोषजनक'', 101 और 200 को ''मध्यम'', 201 और 300 को ''खराब'', 301 और 400 को ''बहुत खराब'' माना जाता है।'', और जब अदक 450 से अधिक हो तो 401 और 450 ''गंभीर'' और ''गंभीर+'' होते हैं।

वर्ली पुलिस को सस्मिरा संस्थान के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने के लिए उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई...

मुंबई : सस्मिरा के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च बर्न घटना के संबंध में दायर एक WRIT याचिका में इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार नौ लोगों को नामित किया गया है, लेकिन वर्ली पुलिस ने केवल एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और अन्य को बख्श दिया है। मृतकों में से एक के पति ने बताया कि कर्मचारियों को काम के समय सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे, और ग्लिसरीन गिरने के लिए जिम्मेदार मशीन की मरम्मत की जरूरत थी। वर्ली पुलिस ने कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण प्रदान करने में विफलता के लिए सस्मिरा संस्थान के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद कार्रवाई की, जिसके कारण पिछले साल दो लोगों की मौत हो गई थी। ''मैंने पिछले साल अपनी पत्नी को खो दिया क्योंकि उसे संस्थान द्वारा सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इस मामले में वर्ली पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज की थी. हालाँकि, मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की और कुछ सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज न करने के लिए वर्ली पुलिस को फटकार लगाई। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और एफआईआर दर्ज की,'' इस घटना के कारण अपनी जान गंवाने वाली श्रद्धा शिंदे के पति एडवोकेट अमर घर्टे ने कहा।

सायन-पनवेल राजमार्ग के किनारे ठाणे खाड़ी में मलबे की अवैध डंपिंग से मैंग्रोव नष्ट हो रहे हैं

महाराष्ट्र : पांच साल पुरानी शिकायत पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में, महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एमसीजेडएमए) ने कोंकण मंडल आयुक्त और राज्य मैंग्रोव समिति से सायन-पनवेल राजमार्ग के साथ ठाणे क्रीक में मलबे द्वारा मैंग्रोव के विनाश की जांच करने के लिए कहा है। शिकायत 1 अगस्त, 2018 को एक गैर सरकारी संगठन, नैटकनेक्ट फाउंडेशन के निदेशक बी एन कुमार द्वारा दर्ज की गई थी, जिसमें निर्माण मलबे के डंपिंग से वाशी और मानखुर्द में मैंग्रोव के विनाश का आरोप लगाया गया था। कुमार ने तीन महीने बाद यही शिकायत पर्यावरण विभाग को भी सौंपी थी. श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठान संगठन के प्रमुख नंद कुमार पवार ने भी विनाश के खिलाफ दिसंबर 2018 में मैंग्रोव समिति के पास इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई थी।

इन सभी वर्षों में, कोंकण संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मैंग्रोव समिति बिना किसी निर्णायक नतीजे के शिकायत से निपट रही थी। पवार ने कहा, ''नतीजा यह है कि मैंग्रोव लगातार नष्ट हो रहे हैं और कोई भी अधिकारी हमारे मौलिक अधिकार के रूप में ज्वारीय पौधों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जिम्मेदारी नहीं ले रहा है।'' कुमार ने अफसोस जताया कि कई अधिकारी और मंत्री राजमार्ग पर यात्रा करते हैं फिर भी किसी को मैंग्रोव की परवाह नहीं है। कुमार ने कहा, ''हम सभी महत्वपूर्ण एमसीजेडएमए के कामकाज की गति से हैरान और भयभीत हैं।''

3 निरीक्षकों को सहायक आयुक्त के पद पर किया पदोन्नत

नवी मुंबईः नवी मुंबई में तीन पुलिस निरीक्षकों को सहायक आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया है। नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त और अन्य अधिकारियों ने इन तीन समर्पित पुलिस निरीक्षकों को अपनी नई भूमिकाओं में सफलता की कामना करते हुए बधाई दी। कई पुलिस निरीक्षक जो सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर पदोन्नति का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन्हें हाल ही में यह पदोन्नति मिली है और इस समूह में विशेष रूप से नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय के तीन पुलिस निरीक्षक शामिल हैं।

महाराष्ट्र पोलीस
सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय
नवी मुंबई पोलीस
Navi Mumbai Police

एपीएमसी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक तनवीर शेख, निरीक्षक घनश्याम अधाव और पुलिस निरीक्षक विजय सिंह भोसले। उनकी सुयोग्य पदोन्नति के बाद, उनमें से प्रत्येक को नई भूमिकाएँ सौंपी गई हैं: शेख अब नवी मुंबई में सीआईडी में एसीपी का पद संभालेंगे।

आधव ने सिंधुदुर्ग में उपविभागीय पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। पुलिस आयुक्त मिलिंद भारम्बे और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों ने जिम्मेदारियों में इन महत्वपूर्ण बदलावों को अंजाम दिया है। तीनों की पदोन्नति को बल के सभी स्तरों पर सहकर्मियों और वरिष्ठों से समान रूप से प्रशंसा और बधाई मिली है।

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : मंगलवार 24 अक्टूबर 2023

शालीमार में सीवेज प्रदूषण से व्यापारी परेशान...

नासिक: शहर के शालीमार इलाके के डॉ. पिछले 15 दिनों से बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के पास का नाला जाम हो गया है और उसका दुर्गंधयुक्त पानी सड़क पर बह रहा है. यह पानी दुकानों के ठीक सामने से शालीमार की ओर बहने से व्यापारियों को परेशानी हो रही है। नागरिकों का आरोप है कि नगर निगम के ड्रेनेज विभाग को बार-बार शिकायत करने के बाद भी अनदेखी की जा रही है. इस संबंध में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने नगर निगम आयुक्त से शिकायत की है. अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष मिलिंद वाई. होंडोर के मार्गदर्शन में एक वक्तव्य दिया गया। इस अवसर पर गोविंदराव गायकवाड, सुभाष गोगुर्डे, राजाभाऊ आवटे, बाला खैरनार, सुरेश पवार, दिलावर मनियार आदि उपस्थित थे।

दुर्गा पूजा उत्सव के लिए बंगाल की राजसी दिव्यता का पुनः निर्माण...

मुंबई : दुर्गा पूजा उत्सव को चिह्नित करने के लिए भारत भर से शानदार प्रतिकृतियां बनाकर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को जीवंत करने की अपनी वार्षिक परंपरा को जारी रखते हुए, भयंदर स्थित, बंगा संघ-एक सामाजिक-सांस्कृतिक-धार्मिक संगठन, ने फिर से बनाया है इस वर्ष कोलकाता का एक राजसी महल मंदिर। कोलकाता के रविशंकर दास के नेतृत्व में कारीगरों की एक टीम द्वारा भयंदर पूर्व के आरएनपी पार्क क्षेत्र में 70 फीट ऊंची पर्यावरण-अनुकूल संरचना स्थापित की गई है। महल की शोभा में चार चांद लगाने वाली है मां दुर्गा की राजसी मूर्ति, जिसकी एक झलक मात्र से गर्मजोशी और आशीर्वाद की अनुभूति होती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और धार्मिक सत्रों से भरे समारोहों के अलावा, सामाजिक जिम्मेदारियों के तहत आयोजक, समाज के वंचित वर्गों की मदद के लिए भी हाथ बढ़ा रहे हैं।

इस वर्ष संगठन ने अनाथालयों और वृद्धाश्रमों में रहने वाले बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा शिविर और विशेष दर्शन सुविधाओं की योजना बनाई है। पांच दिवसीय उत्सव 20 अक्टूबर को शुरू हुआ और 24 अक्टूबर को जुड़वां शहर में समाप्त होगा, जहां बंगालियों की अच्छी खासी आबादी है। ''जाति, पंथ और धर्म के बावजूद, त्योहार न केवल बंगालियों के लिए बल्कि सभी के लिए एक घनिष्ठ समुदाय के रूप में एक साथ आने का एक आदर्श मंच है। इसके अलावा, युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति, विरासत और भाषा को समझने का अवसर मिलता है, ''संगठन के प्रमुख मोंटू जलोई कहते हैं। नित्यानंद पॉल और बसंती घोष ने क्रमशः अध्यक्ष और महासचिव के रूप में पूजा समिति की जिम्मेदारी संभाली है। बंगा संघ, जो दुर्गा पूजा उत्सव के आयोजन के अपने 41वें वर्ष में है, हर साल एक अलग थीम की परिकल्पना करता है। उन्होंने पहले सिक्किम के राजसी नामची (साईं-बाबा) मंदिर और दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर की प्रतिकृतियां बनाई हैं।

पुणे की सड़कों पर चिपकाए गए इजराइल के झंडे के स्टिकर, पुलिस ने 4 मामले दर्ज किये

पुणे: अधिकारियों ने सोमवार को कहा, महाराष्ट्र के पुणे शहर के कुछ हिस्सों में सड़कों पर इजराइल के झंडे की तस्वीर वाले स्टिकर चिपके हुए पाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ चार एफआईआर दर्ज की हैं।

पुलिस के मुताबिक, हमास-इजरायल संघर्ष की पृष्ठभूमि में शुक्रवार देर रात कुछ लोगों ने कथित तौर पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और अनादर करने के इरादे से कोंढवा, भवानी पेठ, नाना पेठ और पुणे छावनी इलाकों में सड़कों पर इजराइल के झंडे के स्टिकर चिपका दिए। अधिकारियों ने बताया कि समर्थ, खड़क, लश्कर और कोंढवा पुलिस स्टेशनों में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसावे देना - अगर दंगा किया जाए - अगर नहीं किया जाए) के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस उपायुक्त (जोन क) संदीप सिंह गिल ने कहा, ''कुछ लोगों ने समर्थ और खडक पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में सड़कों पर इजराइल ध्वज स्टिकर चिपकाए।

हमने पांच लोगों के खिलाफ दो अपराध दर्ज किए हैं।'' डीसीपी (जोन II) स्मार्टना पाटिल ने कहा कि कथित कृत्य के लिए लश्कर पुलिस स्टेशन में चार लोगों के खिलाफ अपराध भी दर्ज किया गया था। एक अन्य अधिकारी ने कहा, इसके अलावा, कोंढवा पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी 8 नवंबर को निकालेंगे 'पारिवारिक मार्च'

मुंबई : महाराष्ट्र में लगभग 17 लाख सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग को लेकर 8 नवंबर को राज्य के हर जिले और तहसील में ''पारिवारिक मार्च'' आयोजित करने का फैसला किया है। 'मेरा परिवार, मेरी पेंशन' के नारे के साथ निकाले जाने वाले मार्च में भाग लेने वाले अपनी मांग पर जोर देने के लिए जिला कलेक्टरों और तहसीलदारों के कार्यालयों तक पहुंचेंगे, राज्य कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों की एक समन्वय समिति के संयोजक विश्वास काटकर , सोमवार को कहा।

2005 में राज्य में ओपीएस बंद कर दिया गया था। ''हमने 8 नवंबर को प्रत्येक जिले और तहसील में 'पारिवारिक मार्च' निकालने और ओपीएस की बहाली की मांग रखने का फैसला किया है। अगर कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो हम 14 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।'' ओपीएस की मांग, ''कटकर ने कहा। कर्मचारी ओपीएस की उनकी मांग को पूरा नहीं करने के कारण महाराष्ट्र सरकार से निराश हैं, जो सेवानिवृत्ति के बाद आय का एक सुनिश्चित और विश्वसनीय स्रोत प्रदान करता है। वे शिक्षा क्षेत्र के अप्रत्यक्ष निजीकरण को रद्द करने और सभी रिक्त पदों को भरने की भी मांग कर रहे हैं। काटकर ने कहा, लगभग 17 लाख सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारी मार्च में भाग लेंगे।

ओपीएस के तहत, एक सरकारी कर्मचारी को उसके अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मासिक पेंशन मिलती है। कर्मचारियों द्वारा अंशदान की कोई आवश्यकता नहीं थी। नई पेंशन योजना के तहत, एक राज्य सरकार का कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देता है और राज्य भी उतना ही योगदान देता है। फिर पैसा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा अनुमोदित कई पेंशन फंडों में से एक में निवेश किया जाता है और रिटर्न बाजार से जुड़ा होता है। राज्य में मराठा समुदाय के सदस्य आरक्षण की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए पहले से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने युवाओं से आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाने का आग्रह किया।

दशहरे पर दादर में यातायात प्रतिबंध!

मुंबई: मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने दादर के सभी निकटवर्ती मार्गों पर नए यातायात परिवर्तन और प्रतिबंधों की घोषणा की है क्योंकि मंगलवार को दादर के शिवाजी पार्क में दशहरा मेलावा समारोह आयोजित किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से भारी भीड़ जमा होने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे आदि जैसी आसपास की सड़कों पर यातायात प्रभावित होगा। कई सड़कें और मार्ग यातायात के लिए बंद रहेंगे, और कई अन्य हैं। पुलिस उपायुक्त, यातायात, डॉ. राजू भुजबल द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, 'नो-पार्किंग' जोन घोषित किया गया है।

चार मार्ग जहां वाहन प्रतिबंधित होंगे और इसका वैकल्पिक मार्ग सिद्धिविनायक मंदिर जंक्शन से माहिम में कपड़ बाजार जंक्शन तक एसवीएस रोड है। वाहन अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए एसके बोले रोड - आगर बाजार - पुर्तगाली चर्च और गोखले रोड का विकल्प चुन सकते हैं। राजा बढ़े चौक जंक्शन से केलुस्कर मार्ग (उत्तर की ओर) जंक्शन मार्ग भी बंद रहेगा। तीसरा बंद मार्ग दक्षिण की ओर यातायात के लिए पांडुरंग नाइक मार्ग पर अपने जंक्शन से लेफ्टिनेंट दिलीप गुप्ते रोड है। मोटर चालक राजा बड़े जंक्शन से होते हुए एलजे रोड की ओर आगे बढ़ सकते हैं। चौथा बंद मार्ग गडकरी चौक जंक्शन से केलुस्कर रोड दक्षिण तक है और वैकल्पिक मार्ग एमबी राउत मार्ग से है। दो अन्य सड़कें जिन्हें सख्ती से बंद किया जाएगा और डायवर्ट किया जाएगा, वे हैं पद्माबाई ठक्कर मार्ग जंक्शन से बाल गोविंदास मार्ग - सेनापति बापट मार्ग से एलजे मार्ग (पश्चिम की ओर) तक।

300 वर्गमीटर तक का घर बनाने के लिए अब CRZ क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं

मुंबई: 300 वर्ग मीटर तक के घरों के निर्माण के लिए सीआरजेड (तटीय विनियमन क्षेत्र) की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ने अब सीआरजेड क्षेत्रों में इस आकार सीमा के भीतर घरों के लिए भवन निर्माण परमिट जारी करने का अधिकार कलेक्टर और स्थानीय निकायों को सौंप दिया है। यह निर्णय केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय के एक निर्देश के जवाब में किया गया था और सदस्य सचिव और पर्यावरण निदेशक अभय पीपरकर के हस्ताक्षर के तहत 18 अक्टूबर, 2023 को एमसीजेडएमए द्वारा अनुमोदित किया गया था। शहर के एक डेवलपर ने कहा, ''यह नवी मुंबई, मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ जिलों, ठाणे के मूल गांव कोलीवाडे और कोंकण तट के साथ सीआरजेड क्षेत्र के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है।'' उन्होंने कहा कि निर्दिष्ट आकार सीमा के भीतर निर्माण अनुमति के लिए सीआरजेड प्राधिकरण से संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह निर्णय 300 वर्ग मीटर से अधिक की बड़ी परियोजनाओं, जैसे कि गोल्फ कोर्स, के निर्माण पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उन्हें अभी भी सीआरजेड मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

मालिक , मुद्रक,प्रकाशक ,संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस , गाला नं 3 - 4 ,अमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट ,सोनावला क्रॉस रोड नं 12 ,गोरगांव (पूर्व),मुंबई 63 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : 1 -ए, ग्राउंड फ्लोर साहिल मेंशन, बालमिया लेन, माहिम वेस्ट मुंबई 400016 मोबाइल नं 9987 77 5650 व्हाट्सप्प नं 7977 40 8589 : Email - editor@rokthoklekhaninews.com